क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 02 अंक: 19, सोमवार, 11 फरवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

राजस्थान की पन्द्रहवीं विधानसभा का दूसरा सत्र सोमवार से होगा शुरु

जयपुर । राजस्थान में पंद्रहवीं विधानसभा का दूसरा सत्र सोमवार से शुरु होगा। सत्र ग्यारह फरवरी को पूर्वाह्न ग्यारह बजे शुरु होगा। इस सत्र में लेखानुदान मांगे पारित करने तथा पहले सत्र में रखा चुनाव में सरपंच चुनने के लिए शैक्षणिक योग्यता समाप्त करने संबंधी राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 तथा शहरी निकायों में पार्षदों की भी शैक्षणिक योग्यता संबंधी नगरपालिका संशोधन विधेयक 2019 पारित किया जायेगा। इसी तरह राजस्थान सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2019 पारित किया जायेगा। अलवर जिले के रामगढ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती कांग्रेस विधायक सफिया खान को शपथ भी दिलाई जायेगी।

राहुल गांधी को 'राफेल फोबिया' है : रविशंकर प्रसाद

हैदराबाद। भाजपा ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह देश की सुरक्षा के साथ काफी 'गैर जिम्मेदाराना तरीके से' खिलवाड़ कर रहे हैं। राहुल राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री पर अक्सर निशाना साधते आ रहे हैं। गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लड़ाकू विमान के सौदे पर वह 'बेशर्मी से झूठ' बोल रहे हैं और उन्हें 'राफेल फोबिया' हो गया है। प्रसाद ने कहा,'राहुल गांधी को राफेल फोबिया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा का वह इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उन्हें शोभा नहीं देता।' गांधी परिवार के सदस्यों पर लगे कथित भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र करते हुए प्रसाद ने कहा, 'बोफोर्स मामले में उनके पिता (राजीव गांधी) पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे? उनकी दादी इंदिरा जी (पूर्व प्रधानमंत्री) के भ्रष्टाचार के क्या रिकॉर्ड रहे हैं? हमने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह की भाषा वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं।' केंद्रीय कानून, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कांग्रेस नीत संप्रग सरकार पर राफेल सौदे को अंतिम रूप नहीं देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इसे फिर समीक्षा के लिए भेज दिया गया क्योंकि पार्टी कोई भी ऐसा समझौता नहीं करती जिसमें उसे 'कमीशन' नहीं मिलता है। उन्होंने कहा, 'चूंकि उन्हें कमीशन नहीं मिला इसलिए उन्होंने इसे (सौदे) लंबित रखा।'2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी ने राफेल सौदे को जारी रखने का निर्णय किया क्योंकि भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमानों की जरूरत है।

यात्रियों को वंदे भारत एक्सप्रेस में देना होगा खाने का चार्ज, नहीं होगा ऑप्शनल

नई दिल्ली: नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 में यात्रियों के लिए खाद्य पदार्थ उनके टिकट का हिस्सा होगा। यानी वह इसे विकल्प की तौर पर 'चुन या हटा' नहीं सकते हैं, जैसा कि शताब्दी, राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस में होता है। अधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को यह जानकारी दी।हालांकि इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन से इलाहाबाद से वाराणसी की यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट बुक कराने के दौरान खाद्य पदार्थ चुनने या नहीं चुनने की सुविधा होगी। यह भोजन भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की ओर से मुहैया कराया जाएगा। कैटरिंग शुल्क उनके टिकट में शामिल नहीं होगा। यह ट्रेन अपनी पहली यात्रा 15 फरवरी को शुरू करेगी। सूत्रों ने बताया कि यात्री अगर टिकट बुक कराने के दौरान भोजन का विकल्प नहीं चुनते हैं, लेकिन वह यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थ चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए अतिरिक्त 50 रुपये देने होंगे। आईआरसीटीसी ने 2017 में राजधानी, शताब्दी और दुरंतो में पैंट्री सिंवस वैकल्पिक कर दिया था। ऐसा यात्रियों से ज्यादा शुल्क वसूलने और गुणवत्ता तथा मात्रा की समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए किया गया था। वहीं ट्रेन18 के बारे में एक अधिकारी ने कहा, ''स्टेशनों के बीच कैटरिंग शुल्क तय कर दिया गया है और यह सभी यात्रियों के टिकट शुल्क में जोड़ा जाएगा।'' ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया प्रीमियम ट्रेनों के मुकाबले अधिक होगा। ट्रेन अपनी 755 किलोमीटर की यात्रा में दो स्टेशनों कानपुर और प्रयागराज में रूकेगी। इस मार्ग पर यह सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाली ट्रेन होगी। यह यात्रा आठ घंटे में तय होगी।

वसंत पंचमी

वसंत पंचमी पर नागा साधुओं ने लगायी संगम में आस्था की डुबकी

कुंभ नगर ।

आस्था के कुंभ में हाथों में तलवार और त्रिशूल और होठों पर हर-हर महादेव के नारे लगाते भस्म से आच्छादित नागा साधुओं ने वसंत पंचमी पर्व पर रविवार को यहां पतित पावनी गंगा, श्यामल यमुना और अन्तः सलिला सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। वसंत पंचमी पर सनातन धर्म का ध्वज चारों ओर फहर रहा था। अखाड़ों के संतों के साथ त्रिवेणी में आस्था का गोता लगाकर श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। पवित्र संगम में ऐसा दिव्य और भव्य कुंभ शायद पहले नहीं देखा गया था। बाल सुलभ क्रीड़ा करते नागा साधुओं के अविस्मरणीय स्नान के दृश्य को दूर खड़े श्रद्धालु निहारते हुये अपनी नजरों में समाहित कर लेना चाह रहे थे। संगम पर त्रिवेणी स्नान के बाद बाहर निकल कर गीले शरीर पर नागा संन्यासी भस्म लपेट रहे थे। सैकड़ों कैमरे उनकी गतिविधियों को कैद कर रहे थे। भीड़ में नागा संन्यासियों का श्रद्धालुओं ने दौड़कर पैर छूने का प्रयास किया जिसका उन्होंने गुस्से से विरोध किया जबकि कुछ ने श्रद्धालुओं को अपने पास आने दिया। संगम तट पर स्नान के दौरान कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई दिया। शैव अखाड़ों के नागा साधुओं का जोश और उत्साह, हाथों में पकड़े दंड वहां मौजूद श्रद्धालुओं को भक्ति भाव से भर रहा था। जैसे ही नागा सन्यासियों की फौज संगम क्षेत्र में पहुंची, दोनों छोरों पर मौजूद श्रद्धालु उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित हो गए। सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के नागाओं ने संगम में स्नान करने से पहले नदियों को प्रणाम किया। गंगा की गोद में अठखेलियां करने के बाद बाहर निकल कर शरीर पर भस्म लगाया और इसके बाद अपने शिविर की ओर कूच कर गये। भस्म शायद कड़कड़ाती ठंड को नियंत्रित करने में सहायक होती है लेकिन कुछ नागा संन्यासी आस्था का गोता लगाने के बाद बाहर निकलने पर ठंड से कांप रहे थे। संगम पर नागा संन्यासियों के स्नान का यह नजारा काफी देर तक दिखाई दिया। लोगों में इस बात की होड़ थी कि कैसे नागा संन्यासियों के स्नान के ठीक बाद पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर वे भी पुण्य का लाभ ले सकें।

गुर्जर आंदोलन हुआ हिंसक: पुलिस वाहनों को लगाई आग; चलाई गोलियां, 6 पुलिसकर्मी घायल

जयपुर ।

पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग लेकर गुर्जरों का आंदोलन रविवार को हिंसक हो उठा। धौलपुर में महापंचायत के बाद गुर्जर आंदोलनकारियों ने एनएच 3 को जाम कर दिया। पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो गुर्जर हिंसा पर उतर आए और पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियां भी फूंक दीं और हवाई फायरिंग की। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को भी हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आंदोलन के तीसरे दिन आज आंदोलनकारियों ने नेशनल हाईवे 148 डी को बूंदी, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा में जाम कर दिया। सोमवार को प्रदर्शनकारी सिकंदरा में हाइवे पर जाम लगा सकते हैं। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में रेल पटरियों पर आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। शनिवार को सरकार की तरफ से पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह व कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार नीरज के पवन गुर्जरों को मनाने मलारना ट्रैक पहुंचे, लेकिन वार्ता विफल हो गई। गुर्जर आंदोलन के कारण कई ट्रेनें रद्द की गईं तो कुछ को रूट बदला गया। गुर्जर आरक्षण सघर्ष समिति जिलाध्यक्ष राधाकृष्ण पोसवाल ने बताया कि सोमवार से जिले में गुर्जर समाज दूध सप्लाई बंद करेगा। सवाईमाधोपुर के मलारना में दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक के अलावा करौली-हिंडौन हाईवे रविवार को भी जाम रहा। उदयपुरवाटी में कोटपूतली-जयपुर स्टेट हाईवे पर जाम रविवार को खोल दिया गया। यहां गुर्जरों ने शनिवार को जाम लगाया था। मलारना में दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक पर रविवार को बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं।

बैसला ने कहा, ट्रैक पर ही होगी बात

गुर्जर नेता किरोड़ीसिंह बैसला ने रविवार को दोहराया कि सरकार से बात रेलवे ट्रैक पर ही होगी। इससे पहले उन्होंने कहा कि सरकार बिना मसौदे के वार्ता के लिए आई थी। जब तक 5 प्रतिशत आरक्षण, क्रीमीलेयर की सीमा 8 लाख रु. करने व पिछली भर्तियों का बैकलॉग से भरी जाने की मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जल्द समाधान की बात कही।

सुप्रीम कोर्ट में है मामला

गुर्जर समाज की मांग है कि सरकार सभी प्रक्रिया पूरी करके पांच प्रतिशत आरक्षण बैकलॉग के साथ दे। इससे पहले 24 सितंबर 2015 को विधानसभा में एसबीसी विधेयक पारित हुआ था। राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2015 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू किया। ये 14 महीने चला और 9 दिसंबर 2016 को हाईकोर्ट ने खत्म किया। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है।

अमेरिका से भारत पहुंचे 4 चिनूक हेलिकॉप्टर, वायुसेना की बढ़ेगी ताकत

नई दिल्ली। एयरोस्पेस कंपनी बोइंग ने रविवार को भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के लिए प्रथम चार सीएच-47एफ (आई) मल्टी-मिशन हेलीकॉप्टर के गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचने की घोषणा की। बोइंग की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि सीएच-47 एफ (आई) चिनूक को चंडीगढ़ भेजा जाएगा, जहां इन्हें औपचारिक रूप से इस साल के अंत में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा।बयान में आगे कहा गया है, सीएच-47 एफ (आई) चिनूक एक उन्नत मल्टी-मिशन हेलीकॉप्टर है, जो भारतीय सशस्त्र बलों को लड़ाकू और मानवीय मिशनों के पूरे स्पेक्ट्रम में बेजोड़ सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता प्रदान करेगा। गौरतलब है कि भारत ने साल 2015 में कुल 15 चिनूक हेलिकॉप्टरों का ऑर्डर अमेरिकी कंपनी बोइंग को दिया था। जिसमें से चार भारत पहुंच चुके हैं। चिनूक के भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने से न केवल सेना की क्षमता बढेगी बल्कि कठिन रास्ते और बॉर्डर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने में भी इसका अहम योगदान रह सकता है। नॉर्थ ईस्ट में कई रोड प्रोजेक्ट सालों से अटके पड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन लंबे समय से एक हेवी लिफ्ट चौपर का इंतजार कर रहा है जो इन घनी घाटियों में सामग्री और जरूरी मशीनों की आवाजाही कर सके। बता दें कि अमेरिकी सेना भी इस हेलिकॉप्टर का उपयोग करती है। अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा बनाया जाने वाला यह एक एडवांस्ड मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। इसमें पूरी तरह से इंटीग्रेटेड, डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन एविएशन आर्किटेक्चर कॉकपिट और एडवांस्ड कार्गो-हैंडलिंग क्षमताएं हैं।

जम्मू-कश्मीर: लालचौक पर आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला, 7 सुरक्षाकर्मी और 4 नागरिक घायल

श्रीनगर ।

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित लाल चौक पर आतंकियों ने रविवार शाम ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान, जम्मू-कश्मीर पुलिस के चार पुलिसकर्मी और 4 आम नागरिक घायल हो गए हैं। घटना ने बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

कुलगाम में 5 आतंकी ढेर

वहीं दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के किलगाम गांव में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड में पांच आतंकवादी मारे गए। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि कुलगाम में आतंकवादियों के छिपे होने की एक गुप्त सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय रायफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दस्ते और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने सुबह क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बल जब क्षेत्र विशेष की तरफ बढ़ रहे थे तो वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर स्वचलित हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने भी इसका करारा जवाब दिया और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में तीन आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है। इस दौरान दो और आतंकवादियों के वहां छिपे होने की जानकारी थी और वे पास के ही एक मकान में छिपे हुए थे। उन्होंने बताया कि मुठभेड स्थल से मलबा हटाकर वहां से आतंकवादियो के शव बरामद करने के बाद जब अभियान दोबारा शुरू किया गया तो मकान में फंसे दो और आतंकवादी मारे गए। कालिया ने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ सेना के अभियान में बाधा पहुंचाने के लिए मौके पर भारी संख्या में आसपास के गांवों के अनेक लोग एकत्र हो गए थे जिन्हें तितर बितर करने के लिए की गई कार्रवाई में 10 लोग घायल हुए हैं।

केन्द्र से मिली धनराशि का इस्तेमाल नहीं कर सके नायडू : मोदी

गुंटूर (आंध्रप्रदेश)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू की कटु आलोचना करते हुए कहा कि तेदेपा प्रमुख राज्य के विकास के वादों से यू-टर्न लेकर सिर्फ राजग सरकार की योजनाओं की नकल का प्रयास कर रहे हैं। मोदी ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने विशेष दर्जा के मुकाबले आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पैकेज को माना/स्वीकार भी किया लेकिन धन का समुचित प्रयोग करने में विफल रहने और राज्य का विकास नहीं कर पाने पर उन्होंने यू-टर्न ले लिया। कांग्रेस-तेदेपा गठबंधन के लिए नायडू पर तंज करते हुए मोदी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एन. टी. रामा राव (एनटीआर) ने कांग्रेस के अहम से पीड़ित होकर आंध्र प्रदेश को 'कांग्रेस मुक्त' बनाने के लिए पार्टी का गठन किया था। उन्होंने कहा कि हां, नायडू उनसे वरिष्ठ हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव हारने, पाला बदलने और अपने ससुर (एनटी रामा राव) को धोखा देने में। उन्होंने कहा कि वह मुझे याद दिलाते रहते हैं कि वह वरिष्ठ हैं। इसमें कोई दो-राय नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि आप वरिष्ठ हैं, मैंने कभी आपका अपमान नहीं किया। आप पाले बदलने में वरिष्ठ हैं। मोदी ने कहा कि अपने ही ससुर की पीठ में छुरा भोंकने वाला वरिष्ठ। एक वरिष्ठ चुनाव-दर-चुनाव हार रहा है, जबकि मैं नहीं। उन्होंने कहा कि यहां तक कि नायडू आज जिसे गालियां दे रहे हैं, कल उसी को गले लगाने में भी वरिष्ठ हैं। मोदी ने आरोप लगाया कि चूंकि केन्द्र ने आंध्र प्रदेश को दिए गए धन के एक-एक पैसे का हिसाब मांगा है, इसलिए नायडू उनके खिलाफ हैं।

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया को खोले जायेंगे

10 मई को खुलेंगे बदरीनाथ के कपाट, बसंत पंचमी के पावन पर्व पर की गई घोषणा

ऋषिकेश ।

बसंत पंचमी के पावन पर्व पर रविवार को बदरीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषणा कर दी गई। ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए तीर्थ पुरोहितों से विचार-विमर्श के बाद राजा मनुजेंद्र शाह की उत्तराधिकारी रानी सीरजा ने कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की। इस साल भगवान बदरी विशाल के कपाट 10 मई को सुबह 4 बजकर 15 मिनट पर पूरे विधान के साथ खोले जाएंगे। वहीं, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया को खोले जायेंगे। आज नरेंद्र नगर राजमहल में राजपरिवार ने विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर भगवान बदरीनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित की। इस साल 10 मई को 4 बजकर 15 मिनट के शुभमहूर्त पर भगवान बदरी विशाल के कपाट खोले जाएंगे। बता दें कि नरेंद्रनगर राजघराने से गाडू घड़ा (तेल कलश) बदरीनाथ पहुंचाया जाता है। फिर इसी तेल से भगवान बदरीनाथ का दीपक जलाया जाता है। इसके बाद विधि विधान से बदरीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। इसके साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खोलने का शुभ मूहूर्त निकाला गया। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीय को खोले जायेंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त शिवरात्रि के दिन उखीमठ में तय किया जाएगा। वहीं, बदरी-केदार मंदिर समिति के धर्माधिकारी ने बताया कि कपाट खुलने की तिथि निकलने के साथ ही चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तरह के प्रयास किये जा रहे हैं। इस बार बदरीनाथ धाम में बहुत अधिक बर्फबारी हुई है, जिसके कारण आसपास के पहाड़ियों में पूरी तरह से बर्फ जमी है। इसका इस बार यात्री आनंद ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।

संपादकीय

ममता बनर्जी जीती तो नहीं हैं...

उच्चतम न्यायालय का आदेश प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना खत्म करने का आधार बना। हालांकि उन्होंने न्यायालय के आदेश को अपनी नैतिक जीत, पश्चिम बंगाल की जीत बता दिया। आखिर इस आदेश में ऐसा क्या है जिसे उनकी जीत माना जाए? पश्चिम बंगाल में जितने दिनों तक ड्रामा चला उसने ममता को नुकसान में ही रखा है। अपने एक अफसर को सीबीआई से बचाने धरने पर बैठना देश के हर आदमी को गलत लगा है।

उच्चतम न्यायालय का आदेश प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना खत्म करने का आधार बना। हालांकि उन्होंने न्यायालय के आदेश को अपनी नैतिक जीत, पश्चिम बंगाल की जीत बता दिया। आखिर इस आदेश में ऐसा क्या है जिसे उनकी जीत माना जाए? न्यायालय ने अभी सीबीआई कर्मियों के साथ पश्चिम बंगाल पुलिस के दुर्व्यवहार पर विचार नहीं किया है। न्यायालय के सामने ममता का विरोध और धरना भी विचार का विषय नहीं था। उसके सामने पहला विषय सीबीआई को कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ की अनुमति देने का था। यह न्यायलय ने दे दिया। उसने पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से ही पूछ दिया कि आखिर उनको सीबीआई के सामने पेश होने में समस्या क्या है? मुख्य न्यायाधीश ने यह भी पूछा कि पश्चिम बंगाल को जांच के हमारे आदेश से क्या दिक्कत है? सीबीआई ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी की अनुमति की अपील की ही नहीं थी। इसलिए यह कहना कोई मायने नहीं रखता कि गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलना सीबीआई के लिए धक्का है।

सीबीआई ने यह कहा ही नहीं था कि वह राजीव कुमार के आवास पर उनको गिरफ्तार करने गई थी। उच्चतम न्यायालय के आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राजीव कुमार को अब सीबीआई के सवालों का जवाब देने शिलांग जाना होगा। इसका अर्थ क्या है? क्या यह ममता सरकार के व्यवहार पर बिना बोले न्यायालय की टिप्पणी नहीं है? इन सबका अर्थ निकालने के लिए हम स्वतंत्र हैं। किंतु जिस तरह सीबीआई की टीम को कोलकाता पुलिस ने अपराधी की तरह पकड़ा, उनको गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए, सीबीआई के संयुक्त निदेशक के घर को घेर लिया गया, क्षेत्रीय कार्यालय को पुलिस घेराव के कारण सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को उतारना पड़ा वो सारे वाकये न्यायालय के सामने थे। आगे ऐसा न हो, इसलिए राजीव कुमार एवं ममता बनर्जी के प्रभाव से बाहर के क्षेत्र में उनसे पूछताछ होगी। वहां राजीव कुमार सामान्य नागरिक होंगे। उनकी सुरक्षा में कोलकाता पुलिस नहीं होगी। चूंकि सारदा चिटफंड एवं रोजवैली घोटाला का मामला सीबीआई को उच्चतम न्यायालय के आदेश से ही मिला है, इसलिए उसके काम में बाधा डालना वास्तव में न्यायालय की भी अवमानना होगी।

सीबीआई ने राजीव कुमार के साथ बंगाल के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र कुमार तथा मुख्य सचिव मलय कुमार डे पर कोर्ट की अवमानना का मामला चलाने की भी अपील की है। इन अधिकारियों ने सीबीआई के अनुरोध की उपेक्षा की। साथ ही पुलिस बल भी इनके मातहत आता है जिसने न्यायालय के आदेश के तहत जांच करने वालों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया तथा सीबीआई के लिए काफी देर तक आतंक का माहौल कायम कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है जिसका जवाब इन्हें 18 फरवरी तक देना है। साथ ही 20 फरवरी को अगली सुनवाई में प्रमुख सचिव, महासचिव और कुमार तीनों को व्यक्तिगत रूप से भी पेश होना होगा। यह किसी तरह अनुकूल आदेश तो नहीं है। अगर न्यायालय ने इन्हें जवाब के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है तो इनकी मेहमानबाजी के लिए नहीं। इनके जवाब से संतुष्ट न होने पर वह कार्रवाई भी कर सकता है। इस आदेश को अगर ममता बनर्जी अपनी जीत, लोकतंत्र की विजय तथा नरेंद्र मोदी और शाह की पराजय कह रही हैं तो टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

उच्चतम न्यायालय का रुख सुनवाई के दौरान हुई टिप्पणियों से भी स्पष्ट हो जाता है। हम यह नहीं कहते कि राजीव कुमार दोषी हैं। वे सक्षम पुलिस अधिकारी माने जाते रहे हैं। उनके नाम कई उपलब्धियां हैं, साहस के कई कारनामे हैं। किंतु इस मामले में उनका रवैया अस्वीकार्य रूप से असहयोगात्मक रहा है यह साफ है। सीबीआई ने यदि उच्चतम न्यायालय में उन पर आरोप लगाए हैं तो उस पर सहसा अविश्वास नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय में एजेंसी झूठा शपथपत्र देगी तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। सीबीआई ने 14 पृष्ठों का जो शपथपत्र दिया है उसमें कॉल रिकार्ड से लेकर आरोपियों से बरामद सबूत नष्ट करने तथा दोषियों को बचाने का आरोप है। न्यायालय ने सीबीआई को केवल गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया, लेकिन पूछताछ के बाद अगर वो छापा मारना चाहती है तो ऐसा करने में कोई रोक नहीं है।

ममता बनर्जी आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बाद दूसरी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 16 नवंबर 2018 को राज्य में सीबीआई के प्रवेश को बैन कर दिया था। दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कानून के अनुसार सीबीआई को राज्यों के मामलों की जांच के लिए सहमति जरूरी है। किंतु सहमति वापस लेने का अर्थ यह नहीं है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी मामले की जांच का आदेश दे तो भी सीबीआई ऐसा नहीं करती। संभव है ममता बनर्जी के फैसले के बाद कुछ अधिकारियों को गलतफहमी हुई हो कि अब सीबीआई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। शायद ममता के कुछ सहयोगियों को भी गलतफहमी रही हो। तो उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यह गलतफहमी दूर हो गई होगी। ममता चाहे इस पूरे प्रकरण का जैसे मूल्यांकन करें, राजीव कुमार के घर पर पहुंचकर तथा धरना देकर उन्होंने सीबीआई का पक्ष मजबूत किया है। सीबीआई को नहीं रोका जाता तो वह उच्चतम न्यायालय शायद ही जाती। अब वह ज्यादा आत्मविश्वास और आक्रामकता से कार्रवाई करेगी।

इस प्रकरण के कई पहलू और हैं जिस पर विचार करना आवश्यक है। चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में मेट्रो सिनेमा से धरना खत्म करते हुए ममता बनर्जी ने कुछ और बातें कहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की एजेंसियों समेत सभी जांच एजेंसियों पर नियंत्रण रखना चाहती है। मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर गुजरात लौट जाना चाहिए। मोदी अपनी दादागिरी चला रहे हैं। कोई भी उनके खिलाफ बोलता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मोदी जी ने संविधान को नष्ट कर दिया, गणतंत्र को नष्ट कर दिया। मेरा कहना है मोदी हटाओ और देश बचाओ। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह पूरा भाषण राजनीतिक है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। इस तरह का भाषण वो लगातार दे रही हैं। प्रश्न है कि इसका सीबीआई की जांच बाधित करने से क्या संबंध है? इसका अर्थ साफ है। ममता लंबे समय से इस रणनीति पर काम कर रही हैं कि उनको मोदी से सीधे टकराने वाली नेता और मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाए। उसके लिए हर अवसर को गलत दिशा देकर टकराव की भंगिमा अख्तियार करती हैं। 19 जनवरी को विपक्षी नेताओं को परेड ग्राउंड में एक मंच पर इकट्ठा कर उन्होंने यह बताने की कोशिश की विपक्ष में मैं अकेले इतनी प्रभावी हूं कि सभी मेरे बुलावे पर आ सकते हैं।

वास्तव में देखें तो इस मामले में ऐसा कुछ नहीं था कि धरना देने की आवश्यकता हो। राजीव कुमार से पूछताछ उनकी पुलिस ने नहीं होने दी। उनकी पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लिया। ममता बनर्जी ने स्वयं कहा था कि हम चाहते तो उनको गिरफ्तार कर सकते थे लेकिन हमने उनको छोड़ दिया। तो इसमें उत्पीड़ित कौन हुआ? सीबीआई या ममता बनर्जी या उनके चहेते अधिकारी? मामला उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सीबीआई की वैध कार्रवाई का था। उच्चतम न्यायालय में बंगाल के वकील ने भी केवल सीबीआई का ही नाम लिया। लोकसभा चुनाव में उनके सामने भाजपा चुनौती बनकर उभर रही है जिसका अंदाजा उनको है। वे यह मानती हैं आम बंगाली का आत्माभिमान इससे उनके पक्ष में जागेगा, लेकिन विवेकशील लोगों को सच पता होगा।

अवधेश कुमार
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

जहरीली शराब पर अंकुश कब

तमाम दावों और घोषणाओं के बाद भी देश में जहरीली शराब का कारोबार थमा नहीं है। यूपी, उत्तराखंड और बिहार में शराब पीने से कई लोग मारे गए हैं। जब तक हमारी सरकारों का नजरिया शराब के जरिए खजाना भरने तक सीमित रहेगा, तब तक समस्या बनी रहेगी।

लाख दावों के बाद भी राज्य में जहरीली शराब के कारोबार पर कोई अंकुश नहीं लग सका है। गांव-गांव कच्ची शराब बनती और बिकती है, पर आश्चर्य है कि पुलिस और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती या यूं कहें कि समूचे तंत्र की शह पर ही मौत का यह कारोबार पनपता है। जिन राज्यों में पूर्ण शराबबंदी लागू है, वहां भी और जहां धड़ल्ले से शराब बिक रही है, वहां भी लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। मगर हमारे नीति-नियंताओं की पेशानी पर बल नहीं दिख रहा है। सरकार और प्रशासन की लापरवाही का शिकार अब उत्तरप्रदेश, बिहार व उत्तराखंड के वे लोग हुए हैं, जो जहरीली शराब पीकर मर चुके हैं और उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। बता दें कि यूपी, उत्तराखंड व बिहार में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। जहरीली शराब का सेवन करने से अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि कई लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों की मौत शराब पीने की वजह से हुई है। देखा जाए तो हर घटना के बाद सरकारें गंभीरता का जो दिखावा करती हैं, वह समय के साथ गायब हो जाता है। फिर अगली घटना तक कोई भी जहरीली शराब पर पाबंदी की बात तक नहीं करता।

जहरीली शराब को लेकर स्थिति इतनी विकट है कि समय-समय पर हर राज्य में किसी न किसी की मौत हो जाती है। वैसे, इस काले कारोबार के लिए सिर्फ पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। राजनीतिक नेतृत्व भी इसके लिए खूब जिम्मेदार है। पार्टी और सरकार कोई भी हो, कभी किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कई नेता तो बाकायदा चुनाव में जीत के लिए अवैध शराब को हथियार बनाते हैं। गरीब-गुरबों को बहलाकर शराब पिलाई जाती है और इस आड़ में अनैतिक काम भी कराए जाते हैं। करने वाले यह नहीं सोचते कि वे देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पीढ़ियां चौपट हो रही हैं, बच्चे स्कूल जाने के बजाय शराब बनवाते हैं और फिर वही उनका पेशा बन जाता है। वहीं इसे पीने वाले आसपास का माहौल खराब करते हैं और अपने घरों का माहौल भी बिगाड़ते हैं। सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या पर अंकुश लगाए, ताकि लोगों को बेमौत मरने से रोका जा सके और समाज का भला हो।

जब तक सरकारों की मौजूदा नीतियां कायम रहेंगी, तब तक शराब की लत की चपेट में आने से लोगों को नहीं बचा सकते हैं। अगर हर गली नुक्कड़ पर शराब की दुकानें खोल देंगे, तो लोग ज्यादा सेवन करेंगे ही। जहां शराब बंदी करने का दिखावा किया जाता है, वहां अवैध बिक्री शुरू हो जाती है और फिर खराब गुणवत्ता वाली शराब बिकने लगती है, जो जानलेवा साबित होती है। शराब के आदी लोग ज्यादा दाम पर भी घटिया शराब पीने लगते हैं, जो मौत के करीब ले जाती है। वैसे भी हर सरकार की कोशिश रहती है कि राजस्व बढ़ाने के लिए शराब के धंधे का ज्यादा से ज्यादा दोहन कर ले। जाहिर है, ऐसे में लोगों को नशे या जहरीली शराब से बचा पाना संभव नहीं है।

नक्सलियों पर कड़ा प्रहार जरूरी

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन चलाकर 10 नक्सलियों को खत्म कर दिया गया। यह बड़ी कामयाबी है। मगर सवाल भी कि आखिर तमाम दावों के बाद भी अब तक नक्सलियों पर लगाम क्यों नहीं कसी जा सकी है। नक्सलवाद खत्म करने के नाम पर जिस तरह के संसाधनों को खर्च किया गया, वह व्यर्थ साबित हो रहा है। नक्सलियों से बातचीत के रास्ते पर चलने को कोई क्यों नहीं तैयार हो रहा है।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन चलाकर 10 नक्सलियों को खत्म कर दिया गया। इस ऑपरेशन को स्पेशल टास्क फोर्स व डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स ने अंजाम दिया था। सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए। इससे पहले बीते शनिवार को भी छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला की जान चली गई थी। नक्सलियों पर नकेल कसने को लेकर सरकार से लेकर सुरक्षा बल तक मुस्तैद हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से 44 जनपदों को बाहर किया जाना इस बात का सूचक है कि केंद्र सरकार नक्सली हिंसा पर लगाम लगाने में एक हद तक सफल हुई है, लेकिन वह इस सफलता पर संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकती और न ही उसे बैठना चाहिए। इसका कारण यह है कि नक्सली संगठन अपनी ताकत बटोरकर नए सिरे से हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने में माहिर हैं। ऐसा कई बार दिख भी चुका है। कई बार वे सुरक्षा बलों की सक्रियता के चलते अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन यह सामने आया है कि वे इस दौरान अपनी ताकत बढ़ाने का काम करते हैं।

यों सुरक्षाबलों का दावा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की ताकत खत्म हो गई है, वे लगातार सिमट रहे हैं, पर इस तरह थोड़े-थोड़े अंतराल पर उनके घात लगा कर या सुनियोजित तरीके से हमलों को अंजाम देने से दावे पर एकबारगी विश्वास नहीं होता है। पहली बात तो यह कि नक्सली योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने में सुरक्षाबल अब नाकाम साबित हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले तर्क दिया गया था कि जिन इलाकों में सड़कों आदि का निर्माण हो रहा होता है, वहां नक्सली बड़ी आसानी से बारूदी सुरंग बिछाने में कामयाब हो जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक बार यह कहा था कि उनके पास बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, जिससे नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं।

यह सही है कि जंगली इलाकों में गश्त करना और नक्सली ठिकानों का पता लगाना सुरक्षाबलों के लिए चुनौतीपूर्ण काम है पर उनके बारे में सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए जरूरी नहीं कि जंगल की खाक छानी जाए। अत्याधुनिक संचार तकनीक के जरिए भी उनकी टोह ली जा सकती है। लंबे समय से यह दावा किया जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ में तकनीकी मदद से नक्सलियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। नोटबंदी के बाद कहा गया कि इससे उन्हें हथियार और दूसरे साजो-सामान उपलब्ध कराने वाले रास्ते बंद हो जाएंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दावा भी किया कि नोटबंदी के बाद नक्सलियों व आतंकवादियों की कमर टूट गई है। पर छत्तीसगढ़ में थोड़े-थोड़े अंतराल पर अगर नक्सली हमले हो रहे हैं, तो इससे यही साबित होता है कि सुरक्षाबलों के पास जैसी तैयारी व प्रशिक्षण होना चाहिए, वह नहीं है। दरअसल, लंबे समय से नक्सलियों को हथियार के बल पर दबाने का प्रयास किया जाता रहा है। कुछ साल पहले आदिवासी समुदाय के लोगों को नक्सलियों से लड़ने के लिए तैयार किया गया और सलवा जुडूम नामक अभियान चला कर उम्मीद की गई कि इस तरह नक्सली आंदोलन समाप्त हो जाएगा। पर वह भी नाकाम साबित हुआ।

नक्सली समस्या से पार पाने के लिए बातचीत का जो सिलसिला बनना चाहिए, वह अभी तक नहीं बन पाया। स्थानीय लोगों में भरोसा पैदा करने की जरूरत पहले है। आदिवासियों का विरोध विकास के नाम पर छीनी जा रही उनकी जमीन और जंगल को लेकर है। अगर सरकारें उन्हें समझाने में कामयाब हो जाएं कि विकास किसलिए जरूरी है व इससे उनके जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे, तो वे शायद नक्सलियों का साथ देना छोड़ देंगे। इसके अलावा, जहां जल, जंगल, जमीन की रक्षा जरूरी है, वहां सरकार को व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करना पड़ सकता है। दमन के सहारे न तो किसी आंदोलन को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है और न ही किसी के मन को बदला जा सकता है। इसलिए नक्सली आंदोलन पर काबू पाने पहले लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है। अगर इस दिशा में कामयाबी मिल गई, तो नक्सली ताकतें अपने आप समाप्त हो जाएंगी।

नक्सली हमलों पर काबू पाने के मकसद से विभिन्न राज्यों में अब तक अनेक उपाय आजमाए जा चुके हैं, मगर इस समस्या का हल निकाल पाना चुनौती बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रभाव समाप्त करने के मकसद से सलवा जुडूम जैसे प्रयोग किए गए और सुरक्षा बलों को अधिक चौकस बनाने का प्रयास किया गया, मगर इन सबका खास असर नहीं दिखा। इसी तरह बिहार राज्य के जंगली इलाकों में नक्सलियों के दबदबे को खत्म करना कठिन बना हुआ है। सवाल है कि क्यों इस समस्या पर काबू पाने में कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही। नक्सली नेटवर्क को भेदने के लिए सुरक्षा बलों को विशेष प्रशिक्षण देने, संचार तंत्र को मजबूत करने और खुफिया तंत्र को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। फिर भी स्थिति यह है कि नक्सली संगठनों के पास अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद पहुंच रहे हैं। उनकी योजनाओं का पता लगाना कठिन बना हुआ है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि औरंगाबाद के जंगलों में नक्सलियों से निपटने के लिए वहां की सरकार ने कोबरा नाम से विशेष सुरक्षा दस्ता गठित किया है। वही दस्ता जंगलों में गश्त पर था, तो हमला हो गया। इसमें आईईडी विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। घटना स्थल से एके सैंतालीस, इंसास राइफलें और ग्रेनेड लांचर बरामद हुए। सवाल यह है कि ऐसे साजो-सामान नक्सलियों तक किस तरह पहुंच रहे हैं। उनकी आपूर्ति पर सुरक्षा और खुफिया तंत्र नजर क्यों नहीं रख पा रहा है।

नक्सल समस्या पर काबू नहीं पाए जा सकने का बड़ा कारण हमारी सरकारों का उनके साथ बातचीत का व्यावहारिक सिलसिला शुरू न कर पाना और उन्हें विश्वास में न ले पाना भी है। फिर जिस तरह का तालमेल सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों, स्थानीय पुलिस और नागरिकों के साथ बनना चाहिए, वह नहीं बन पा रहा है। नक्सलियों की लड़ाई सैद्धांतिक स्तर पर शुरू हुई थी, मगर अब वह अपनी दिशा खो चुकी है। उनके विभिन्न संगठनों से तालमेल हो चुके हैं, जहां से उन्हें गुरिल्ला प्रशिक्षण और साजो-सामान उपलब्ध हो रहे हैं। यह भी छिपी बात नहीं है कि अनेक जगहों पर नक्सलियों के दबदबे से लोग परेशान हैं। वे जबरन वसूली जैसे कामों में भी शामिल हो गए हैं। फिर भी सुरक्षा बल उनकी लड़ाई को कमजोर करने में स्थानीय लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं और अवैध रास्तों से उपलब्ध हो रहे साजो-सामान पर नजर नहीं रख पा रहे हैं तो यह उनकी भारी विफलता है। स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर ही नक्सली प्रभाव को कमजोर किया जा सकता है, पर सुरक्षा बल प्रायः सख्ती अपना कर उनसे सूचनाएं हासिल करने का प्रयास करते देखे जाते हैं। सरकारों ने कभी गंभीरता से नक्सली संगठनों के साथ बातचीत करने का प्रयास नहीं किया।

पूर्वोत्तर के कई विद्रोही संगठन जब बातचीत के जरिए अपना हिंसक रास्ता छोड़ने को तैयार हो सकते हैं, तो नक्सलियों को बातचीत के जरिए समझाना क्यों कठिन होना चाहिए! कई मामले सख्ती के बजाय लचीला रुख अपना कर भी हल किए जा सकते हैं। अगर नक्सल समस्या का बारीकी से अध्ययन कर व्यावहारिक रास्ता निकाला जाए तो हिंसक प्रवृत्ति पर काबू पाना शायद कठिन नहीं होगा।

राकेश दीक्षित
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

ट्विटर

जहरीली शराब के शिकार लोगों के प्रति संवेदना है। उन लोगों को भी कतई नहीं छोड़ा जाएगा, जो जिम्मेदार हैं। मामले की जांच जारी है। सख्त कार्रवाई होगी।

केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री यूपी

जहरीली शराब के कारोबारियों को पकड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने प्रशासन को सख्त आदेश दिया है कि जो कोई भी जिम्मेदार हो, उसे छोड़ा न जाए।

त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

सत्यार्थ

अपना काम करते रहें

एक बार ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की कि उनके गांव में सात साल तक पानी नहीं बरसेगा। यह सुनकर सभी गांववासी निराश हो गए और गांव छोड़कर जाने लगे। लेकिन एक किसान को अपने गांव से बेहद प्रेम था, इसलिए वह वहीं डटा रहा। उसने सोचा कि सात वर्ष तक वर्षा तो होनी नहीं है, फिर हल वगैरह का क्या काम? उसने उन्हें उठाकर एक तरफ रख दिया। किसान ने सोचा कि हल वगैरह तो उसने एक तरफ रख दिए, लेकिन यदि सात साल में उन्हें चलाना ही भूल गया तो? इसलिए वह हल उठाकर खेत जोतने लगा। उसने सोचा कि भले ही वर्षा न हो, पर इससे खेती का अभ्यास तो बना रहेगा। कई दिनों तक वह लगातार खेत जोतता रहा। एक दिन एक बदली वहां से निकली। अभी तक ऐसी अनेक बदलियां वहां से बिना बरसे ही निकल चुकी थीं, पर यह बदली किसान को खेत जोतते हुए देखकर रुकी और बोली- तूने सुना नहीं कि यहां सात साल तक वर्षा नहीं होगी, फिर तू व्यर्थ में ही खेत को क्यों जोत रहा है? तब किसान बोला-मत बरसो, मैं तो खेत को इसलिए जोतता हूं कि कहीं सात साल में खेत जोतना ही न भूल जाऊं। यह सुनकर बदली हैरान हो गई व सोचने लगी कि कहीं सात साल में मैं भी बरसना न भूल जाऊं। वह बरसने लगी। उसे बरसता देख अन्य बदलियां भी इकट्ठी हो गईं और बदली की बरसना भूलने वाली बात सुन सभी उसका साथ देते हुए बरसने लगीं। इस तरह काम की आदत व श्रम ने भविष्यवाणी को झुठला दिया। तात्पर्य यह कि हम अंधविश्वास में पड़कर किसी भविष्यवाणी को सच न मानें, बल्कि अपने काम पर ध्यान दें। प्रकृति भी उन्हीं लोगों का साथ देती है, जो अपने काम में लगे रहते हैं, उस किसान की ही तरह।

रेनू सैनी

शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 53,741 करोड़ बढ़ा

नयी दिल्ली। सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों में से आठ का बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) बीते सप्ताह 53,741.36 करोड़ रुपये बढ़ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस का बाजार पूंजीकरण सर्वाधिक बढ़ा है। शीर्ष 10 कंपनियों में से सिर्फ आईटीसी और एचडीएफसी का बाजार पूंजीकरण ही बीते सप्ताह कम हुआ। फायदे में रही अन्य कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस के अलावा एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शामिल रहीं। रिलायंस का बाजार पूंजीकरण 19,047.69 करोड़ रुपये बढ़कर 8,09,669.50 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह, टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 12,007.64 करोड़ रुपये बढ़कर 7,74,023.16 करोड़ रुपये, एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 8,569.51 करोड़ रुपये बढ़कर 5,77,598.58 करोड़ रुपये हो गया।

कोटक महिंद्रा बैंक का बाजार पूंजीकरण 7,144.30 करोड़ रुपये बढ़कर 2,47,151.12 करोड़ रुपये, हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 4,578.23 करोड़ रुपये बढ़कर 3,93,403.30 करोड़ रुपये, इंफोसिस का बाजार पूंजीकरण 1,441.65 करोड़ रुपये बढ़कर 3,31,951.71 करोड़ रुपये, भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण 669.35 करोड़ रुपये बढ़कर 2,54,395.37 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 282.99 करोड़ रुपये बढ़कर 2,28,644.74 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं, दूसरी ओर आईटीसी का बाजार पूंजीकरण 6,063.49 करोड़ रुपये कम होकर 3,37,901.54 करोड़ रुपये और एचडीएफसी 2,931.69 करोड़ रुपये कम होकर 3,34,256.62 करोड़ रुपये पर आ गया। शीर्ष 10 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर रही। इसके बाद टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एचडीएफसी, इंफोसिस, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का स्थान रहा।

देश में एम्स जैसे और संस्थान खोले जा रहे हैं : जेपी नड्डा

चंडीगढ़। केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने शनिवार को कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में एम्स जैसे कई संस्थान खोल रहा है और मेडिकल कॉलेजों के नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नड्डा यहां स्नात्तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) के 35 वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। नड्डा इस संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। नड्डा ने केंद्र सरकार की पहलों का जिक्र करते हुए कहा, ''हम देश के विभिन्न हिस्सों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थान खोल रहे हैं। हम बड़े पैमाने पर जिला अस्पतालों का मेडिकल कॉलेजों के रूप में उन्नत कर अपने मेडिकल कॉलेजों के नेटवर्क का भी विस्तार कर रहे हैं। '' उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाएं लाने से गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में पूर्ण बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) को 31 अक्टूबर,2018 को पीजीआईएमईआर में लागू किया गया और उसके तहत करीब 177 मरीजों का इलाज किया गया। दीक्षांत समारोह में पीजीआईएमईआर के 1886 विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में डिग्रियां प्रदान की गयी। केंद्रीय मंत्री ने उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए 35 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। इसके अलावा 92 को रजत पदक और 95 को कांस्य पदक प्रदान किये गये।

भारतीय बाजार पर बढ़ा निवेशकों का भरोसा, 6 दिनों में 5300 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश

नई दिल्ली। विदेशी निवेशकों ने पिछले छह कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजारों में करीब 5,300 करोड़ रुपये का निवेश किया है. निवेशकों ने आर्थिक वृद्धि दर ऊंची रहने की उम्मीदों के चलते यह रुख अपनाया. इससे पहले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जनवरी महीने में शेयर बाजारों से 5,264 करोड़ रुपये निकासी की थी. वहीं, नवंबर-दिसंबर 2018 के दौरान उन्होंने शेयर बाजारों में 5,884 करोड़ रुपये का निवेश किया था. आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने एक से आठ फरवरी के दौरान शेयर बाजारों में 5,273 करोड़ रुपये का निवेश किया. हालांकि, इसी अवधि में उन्होंने ऋण बाजार से 2,795 करोड़ रुपये की निकासी की. विश्लेषकों ने कहा कि जनवरी में शुद्ध रूप से बिकवाली के बाद फरवरी में विदेशी निवेशक अब तक शुद्ध लिवाल बने हुए हैं. यह एक स्वागत योग्य कदम है हालांकि, अभी महीना शुरू ही हुआ है और ऐसे में निवेशकों का रुख किस तरफ होगा यह कहना जल्दबाजी होगी.

देशी नहीं विदेशी अर्थशास्त्री भी कर रहे मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

फ्रांस के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गॉय सोरमैन ने रविवार को नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की सकारात्मक और सुसंगत नीतियों ने भारतीय उद्यमियों के लिये बेहतर कारोबारी माहौल तैयार किया है. सोरमैन ने पीटीआई- भाषा के साथ एक साक्षात्कार में कहा, ''किसी को भी किसी सरकार से आर्थिक चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिये. यह कहा जा सकता है कि मोदी सरकार की नीतियां सकारात्मक और सुसंगत रही हैं. उन्होंने कम मुद्रास्फीति और अपेक्षाकृत कम भ्रष्टाचार के साथ उद्यमियों को पहले से बेहतर माहौल दिया है.''

सोरमैन ने 'इकोनॉमिक्स डज नोट लायर ए डिफेंस ऑफ दी फ्री मार्केट इन ए टाइम ऑफ क्राइसिस' समेत कई किताबें लिखी हैं. उन्होंने कहा कि वित्तीय बाजार में सकारात्मक बदलाव, निवेश में वृद्धि तथा जीडीपी की ऊंची वृद्धि दर के लिये सरकार की नीतियों को श्रेय जाता है. उन्होंने कहा, ''मोदी की अर्थनीति सकारात्मक रही है और जहां तक मुझे ध्यान है, यह पिछली किसी भी सरकार से काफी बेहतर है.''

अंतरिम बजट में छोटे किसानों के लिये छह हजार रुपये सालाना की वित्तीय सहायता के बारे में पूछे जाने

पर उन्होंने कहा कि गरीब और पिछड़े लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने को अब अर्थशास्त्री भी गरीबी दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका मानने लगे हैं. उन्होंने कहा, ''इस आधार पर इस तरह की आर्थिक सहायता को सही कहा जा सकता है.''सोरमैन ने वृद्धि तथा रोजगार को लेकर हालिया विवाद के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत व्यापक रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित देश है जहां अनौपचारिक और वस्तु विनिमय चलन में है. ऐसे में आंकड़े जुटाना मुश्किल काम है. उन्होंने कहा, ''सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा प्रति व्यक्ति आय का होता है न कि राष्ट्रीय जीडीपी. यह भी बुद्धिमतापूर्ण होगा कि अधिक विश्वसनीय आंकड़े जमा करने के लिये सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए.''

केंद्र सरकार के विभागों में आने वाली हैं 1.3 लाख नौकरियां, रिपोर्ट का दावा

नई दिल्ली। देश में बेरोजगारी बढ़ने पर चल रही बहस के बीच मोदी सरकार ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में साल 2017 और 2019 के बीच 3.79 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित होने का दावा किया. सरकार ने कहा कि उसने 2017 और 2018 के बीच केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में 2,51,279 नौकरियां सृजित की. वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा एक फरवरी को पेश किए अंतरिम बजट के दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चलता है कि एक मार्च 2019 तक सरकार द्वारा सृजित नौकरियां 3,79,544 तक बढ़कर 36,15,770 पर पहुंच जाएंगी.

यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बेरोजगारी बढ़ने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं. सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया है. संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर गुरुवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मोदी ने कर्मचारी भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना, आयकर फाइलिंग और वाहनों की बिक्री के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि परिवहन, होटलों और ढांचागत समेत औपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रों में छह करोड़ नयी नौकरियां पैदा की गई.

ज्यादातर भर्तियां, रेल मंत्रालय, पुलिस बलों और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आयकर विभागों ने की. बजट के दस्तावेजों में सेक्टर-वार ब्यौरा दिया गया है कि कैसे केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में नौकरियों का सृजित किया गया. दस्तावेजों के अनुसार, भारतीय रेलवे एक मार्च 2019 तक सबसे अधिक 98,999 नौकरियों का सृजन करेगा. पुलिस विभागों में एक मार्च 2019 तक 79,353 अतिरिक्त नौकरियां सृजित की जाएगी. इसी तरह डाक विभाग में एक मार्च 2019 तक 4,21,068 कर्मचारी होंगे.

जन धन खातों में कुल जमा 90,000 करोड़ रुपये के पार जाने को तैयार

नई दिल्ली (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री जन धन खातों में कुल जमा जल्द ही 90,000 करोड़ रुपये के स्तर को पार जा सकती है। सरकार ने वित्तीय समावेश वाली इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा कवर को दोगुना करके 2 लाख रुपये कर दिया जिससे योजना और आकर्षक हो गई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2017 से जन धन खातों में जमा में तेजी आई है। इन खातों में 30 जनवरी 2019 तक कुल जमा बढ़कर 89,257.57 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। जमा में वृद्धि जारी है। 23 जनवरी को कुल जमा 88,566.92 करोड़ रुपये थी।

सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) शुरुआत की थी। योजना की सफलता से उत्साहित सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए खातों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया। ओवरड्राफ्ट की सीमा को दोगुना करके 10,000 रुपये कर दिया गया है।

नए आंकड़ों के मुताबिक, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 34.14 करोड़ खाते खोले गए हैं। इन खातों में औसत जमा बढ़कर 2,615 रुपये हो गई, जो कि 25 मार्च 2015 को 1,065 रुपये पर था। इन खातों में 53 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं, जिसमें से 59 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र से है। आंकड़ों के मुताबिक, 27.26 करोड़ खाताधारकों को दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं।

सरकारी योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से 90,000 करोड़ की बचत : मनोज सिन्हा

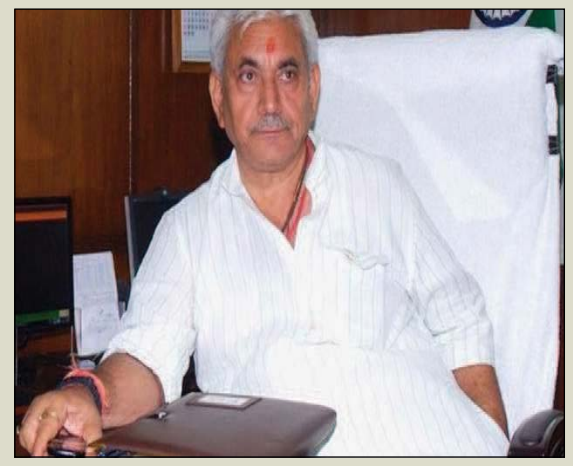

नयी दिल्ली। केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने सरकारी योजनाओं में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से सरकार ने एक साल में 90 हजार करोड़ रुपये बचाए हैं। इसके आगे और भी बढ़ने की गुंजाइश है। सिन्हा यहां विज्ञान भवन में एक स्वयंसेवी संस्था अष्टव्रत इंडिया फाउंडेशन की ओर से ÷सामाजिक उद्यमिता एवं उसके माध्यम से समाज के विकास÷ विषय पर संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। सिन्हा ने कहा, ÷सरकारी सहायता और लाभ को सीधे लाभार्थियों के खाते में डालने से सालभर में 90 हजार करोड़ रुपये बचे हैं।'

उन्होंने सवालों के जवाब में कहा कि सरकार भारत नेट योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के जरिए सरकारी सेवाएं पहुंचने की बड़ी योजना चला रही है। साझा सुविधा केंद्रों (सीएससी) के जरिए 115 तरह की सेवाएं दी जा रही हैं। इनमें जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से लेकर बैंकिंग सुविधायें तक शामिल हैं। भविष्य में पांच लाख गांवों को डिजिटल प्रौद्योगिकी से जोड़ने का लक्ष्य है। सिन्हा ने कहा कि देश की तकदीर तकनीक है और तकनीक के माध्यम से लोगों को सशक्त करना, जोड़ना और उनकी सामूहिक ताकत को जागृत करना आसान हुआ है।

उन्होंने देश के ग्रामीण इलाकों में ऑप्टिक फाइबर केबल के माध्यम से दो लाख गांवों में साझा सेवा केन्द्र खोले जाने का उल्लेख किया और कहा कि इससे गांवों में लोगों को डिजिटल माध्यम से मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से लेकर बैंकिंग सुविधायें तक इन सेंटरों में मिल रहीं हैं। कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य एवं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख डॉ विवेक देवराय, स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय शंकर और दिल्ली विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की डीन प्रो. सुनीता सिंह सेनगुप्ता ने भी भाग लिया।

कटोरा लेकर दुबई पहुंचे इमरान खान, राहत पैकेज को लेकर आईएमएफ चीफ से होगी मुलाकात

इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान राहत (बेलआउट) पैकेज की शर्तों पर चर्चा के लिये रविवार को दुबई में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड से मुलाकात करेंगे. खान वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के सातवें संस्करण में भाग लेने के लिये संयुक्त अरब अमीरात की एक दिन की यात्रा पर गए हैं. पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने डॉन अखबार से कहा कि खान सम्मेलन से इतर दुबई में लगार्ड से मुलाकात करेंगे. अखबार की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि लगातार बातचीत के बाद पिछले कुछ सप्ताह में आईएमएफ और पाकिस्तान का रुख संकुचित हुआ है.

आईएमएफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिये कुछ सुधारात्मक कदम उठाने की शर्त रख रहा है.

वह चाहता है कि पाकिस्तान अगले तीन-चार साल में करीब 1,600-2,000 अरब रुपये का समायोजन करे. बातचीत में पाकिस्तान के खर्च को लेकर भी रोड़ा अटक रहा है.

बता दें, पिछले दिनों सरकार ने हज सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया. इससे पाकिस्तान सरकार के 450 करोड़ रुपये की बचत होगी. पाकिस्तान के धार्मिक एवं आपसी सौहार्द मामलों के मंत्री नूरुल हक कादरी ने यह जानकारी दी. हज सब्सिडी खत्म करने का फैसला हाल में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता वाली संघीय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया, जिससे इस बात पर बहस छिड़ गयी है कि क्या इस्लाम सब्सिडी युक्त हज की इजाजत देता है.

इस साल 184,000 पाकिस्तानी नागरिक हज यात्रा करेंगे

'द न्यूज' ने कादरी के हवाले से मंगलवार को कहा, 'पूर्ववर्ती (पीएमएल-एन) सरकार हर हज यात्री को 42-42 हजार रुपये की सब्सिडी देती थी जिससे राजकोष पर 450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ता था. देश की मौजूदा आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए संघीय कैबिनेट ने इस सब्सिडी को खत्म करने का फैसला किया है.'

देश के हर घर में जल्द ही खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन होगा : प्रधान

ग्रेटर नोएडा (उर प्रदेश) (एजेंसी)।

सरकार ने महज 55 महीनों में एलपीजी का दायरा करीब 40 प्रतिशत बढ़ाने में सफलता हासिल की है। सरकार का लक्ष्य अब जल्द ही हर घर में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने का है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को यह बात कही। प्रधान ने पेट्रोटेक 2019 सम्मेलन में कहा कि देश में 2014 में एलपीजी की पहुंच 55 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 90 प्रतिशत के करीब पहुंच गई है। उन्होंने कहा, 'जल्द ही देश के सभी घर खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन से जुड़ जाएंगे। ईंधन की आपूर्ति एलपीजी के साथ-साथ बायो-मास और वैकल्पिक स्त्रोतों से होगी।'

प्रधान ने कहा कि देश में एलपीजी का दायरा बढ़ाने का श्रेय प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) को जाता है, जिसने गरीबों को मुफ्त रसोई गैस की सुविधा दी। इस योजना के तहत एक मई 2016 से अब तक करीब 6.4 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं। एक मई 2016 को उज्जवला योजना शुरू हुई थी। उन्होंने कहा, 'इस योजना के अंतर्गत हम 31 मार्च 2020 से पहले आठ करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देंगे।÷ माना जा रहा है कि एलपीजी को ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई में इस्तेमाल वाले पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी और कंडे की जगह लेनी चाहिए। ये न केवल पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डालते हैं।

प्रधान ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र का अहम योगदान है और 2017 में यह हमारी कुल ऊर्जा जरूरतों का करीब 55 प्रतिशत था। भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वैश्विक तेल खपत में उसकी हिस्सेदारी 4.5 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, 'हमने हाइड्रोकार्बन नीति की रूपरेखा में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।' खोज एवं उत्पादन तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करते हुए पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि राजस्व साझा करने के लिए नया प्रारूप, सभी हाइड्रोकार्बनों के लिए एक ही लाइसेंस और पेट्रोलियम एवं गैस के लिए विपणन स्वतंत्रता जैसी चीजों को पेश किया गया है।

गुजरात में स्वाइन फ्लू का कहर, 24 घंटों में 11 मरीजों की मौत

सूरत। गुजरातभर में स्वाइन फ्लु ने हाहाकार मचा रखा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में स्वाइन फ्लु से 11 लोगों की मौत हो गई। राजकोट में स्वाइन फ्लु दो, वडोदरा में एक मरीज की मौत हो गई। इसी के साथ जारी सीजन में स्वाइन फ्लु से मौत का आंकड़ा बढ़कर 62 पर पहुंच गया है। राजकोट में स्वाइन फ्लु के । नए केस सामने आए हैं। वहीं वडोदरा जिले में भी स्वाइन फ्लु के 10 पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं। राज्यभर में करीब 400 जितने स्वाइन फ्लु ग्रस्त मरीज उपचाराधीन हैं। केवल वडोदरा में स्वाइन फ्लु के ।6 मरीजों का उपचार चल रहा है। अहमदाबाद में स्वाइन फ्लु के सबसे अधिक केस सामने आएं हैं। सूरत,

वडोदरा, राजकोट में स्वाइन फ्लु ने हाहाकार मचा रखा है। अहमदाबाद महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने बीमार बच्चों को स्कूल में नहीं भेजने का आदेश दिया है। अहमदाबाद में पिछले डेढ़ महीने में स्वाइन फ्लु के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। जनवरी के मुकाबले फरवरी माह की स्थिति काफी चिंताजनक है। फरवरी के केवल सात दिनों में 200 से ज्यादा स्वाइन फ्लु के मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि स्कूल में बीमार बच्चों का ध्यान रखा जाए और इसके लिए अभिभावकों के साथ बैठक भी करने की ताकीद की गई है। गौरतलब है अहमदाबाद में पिछले चार दिनों में स्वाइन फ्लु के 2 मरीजों की मौत हो गई है। ठंड का प्रकोप बढ़ने से आगामी समय में स्वाइन फ्लु के फैलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

गुजरात में स्वाइन फ्लु के लगातार बढ़ते केस को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में औचक जांच की। जहां स्वाइन फ्लु ग्रस्त मरीजों के उपचार और व्यवस्था इत्यादि की जांच की। अहमदाबाद में स्वाइन फ्लु के केस और मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। मौत और व्यवस्था के बारे में केन्द्रीय टीम निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपेगी।

प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराते दो पादरी गिरफ्तार

नवसारी। गुजरात में धर्मांतरण के मामले में दो पादरियों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात में धर्मांतरण को लेकर गिरफ्तारी की यह पहली घटना है। इस घटना से धर्मांतरण कराने वाले लोगों में हड़क प मच गया है। पिछले काफी समय से गुजरात में ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा हिन्दू हलपति समाज के लोगों को आए दिन धर्म परिवर्तन कराने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिसमें ना ना प्रकार के प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अंगीकार करवाया जाता है। ऐसे ही मामले में नवसारी की बिलीमोरा पुलिस ने दो पादरियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कुछ समय पहले दक्षिण गुजरात के कई गांव के लोगों ने गांव के बाहर पोस्टर लगाए थे। जिसमें कहा गया था कि ईसाई धर्म के अनुयायियों के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध है।

सणिया हेमद गांव के निकट खाडी में दो किशोर डूबे, तलाश जारी

सूरत। शहर की सीमा स्थित सणिया हेमद गांव के निकट खाडी में जा गिरे। यह घटना उस समय हुई जब दोनों किशोर स्कूल से अपने घर की ओर लौट रहे थे और खाडी पर रखे लोहे एंगल से गुजरते समय उनका पैर फिसल गया और एक के बाद एक पानी में जा गिरे। घटनास्थल पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम दोनों किशोरों की तलाश कर रही है।

जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मूल निवासी राजुभाई दुर्वे की वर्षों से सूरत के कुंभारिया में रहते हैं और मजदूरी कर परिवार का जीवनयापन करते हैं। आज दोपहर राजुभाई के दो पुत्र शिवा और मनोज स्कूल से छूटकर घर की ओर आ रहे थे। उस वक्त ट्रांसपोर्ट गोदाम के निकट खाडी पर निर्माणाधीन ब्रिज के बगल में रखे लोहे एंगल से खाडी पार कर रहे थे। उस दौरान अचानक दोनों भाइयों का पैर फिसल गया और दोनों खाडी के गंदे पानी में जा गिरे। आसपास के लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और दोनों किशोरों की खोजबीन शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बावजूद देर शाम दोनों किशोरों की कोई खैर खबर नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड की टीम खाडी में दोनों की तलाश कर रही है। गौरतलब है खाडी पार करने के लिए उस पर रखी लोहे की एंगल जोखमी होने के बावजूद ठेकेदार द्वारा इसे हटाया नहीं गया। जबकि आए दिन लोग यहां से गुजरते हैं। आज दो किशोरों के एंगल से फिसलकर खाडी में गिरने की घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश भड़क उठा है।

अहमदाबाद शहर के चंडोला तालाब क्षेत्र में सुबह में झोपडपट्टी में आग लग गई थी। जिसमें कई झोपड़ी जलकर खाक हो गये। काफी प्रयास के बाद फायरब्रिगेड ने आग को नियंत्रण में ले लिया।

मनीष दोशी का रुपाणी के काम पर सवाल

पिछले दो साल में राज्य में १३,५७४ महिला गुम हुई

४२४३२ बच्चे लापता इसमें से १४८८१ बच्चे लंबे समय से लापता, लापता व्यक्तियों को ढूढ़ने में प्रशासन विफल

अहमदाबाद । राज्य में महिलाओं को सुरक्षा देने की और बेटी बचाओ-बेटी पढाओ के नारे देने वाली भाजपा की राज्य सरकार महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की चिंता नहीं करती है । सरकारी खर्च सिर्फ महिला सम्मेलनों को आयोजित करने और नारे में देने में किया जाता है जबकि पिछले दो वर्ष में राज्य में से १३,५७४ महिलाएं लापता हुई है । राज्य में बच्चे लापता होने के आंकड़े राज्य सरकार और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री की विफलता का आरोप लगाते हुए गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता डॉ. मनीष दोशी ने बताया कि जिस तरीके से आंकड़े सामने आये इसमें विशेष करके बेटी कितनी है यह जांच का विषय है । मानव तस्करी रोकने के लिए राज्य सरकार सक्रिय हो यह बहुत ही जरूरी है । दो वर्ष में राज्य में ४,९८९ बच्चे लापता हुए हैं । राज्य सरकार के आधिकारिक आंकड़े के अनुसार राज्य में से ४२,४३२ बच्चे लापता हुए हैं इसमें से १४,८८१ बच्चे लंबे समय से लापता है, जबकि १४,३०१ व्यक्ति लापता है यह लापता व्यक्तियों को ढूढ़ने में प्रशासन विफल हो गया है । राज्य में और देश में लापता हुए बच्चों, महिलाओं के मामले में पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष २०१२-१३ में राज्य के मुख्य सचिव को राज्य में से लापता हुए बच्चों की जानकारी पेश करने के लिए दो बार नोटिस भेजी गई थी फिर भी राज्य सरकार जानकारियों को पेश नहीं कर सकी । इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए लापता हुए बच्चों के मामले में संबंधित समय में आंकड़ा पेश किया गया था । राज्य में लापता हुए बच्चों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों को दिए आदेश में अंतरराज्यीय एकीकरण, राज्य में विभिन्न जिलों में संकलन, लापता हुए बच्चों की जानकारियां प्रदर्शित करती वेबसाइट, लापता हुए बच्चों की हेल्पलाइन सहित की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है । अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में बच्चे लापता होने के मामले में पीसीबी को जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन अभिभावक लापता हुए बच्चों के मामले में शिकायत करने जाए तो पीसीबी अपने क्राइमब्रांच के मीसींग चाइल्ड सेल में भेजते है।

घटना की वजह से जूनागढ़ क्षेत्र में शोक की लहर

कल्याणधाम निकट कार पलटने से ४ युवक की मौत

मृतक युवकों में से एक युवक की बहन की आज शादी थी, शादी की खुशी का प्रसंग अब शोक में बदल गया

अहमदाबाद । जूनागढ़ के मांगरोल के पोरबंदर रोड पर स्थित कल्याणधाम निकट रविवार को सुबह में एकदम स्पीड में कार के चालक ने स्टियरिंग पर से नियंत्रण गंवाने से कार पलटने से गांव के बस स्टेन्ड में घुसी गई थी। कार में सवार चार युवक नीखिल वाला, वीकी पीठवा, मोहित राजा कोडीयातर और देवा दिनेशभाई करमटा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना की वजह से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई । विशेष करके युवकों के गांववाले क्षेत्रों में शोक की लहर फैल गई। इस भीषण दुर्घटना में आश्चर्य की बात तो यह थी कि, चार मृतक युवकों में से एक युवक की बहन की रविवार को शादी थी और यह युवक भी इस दुर्घटना में मौत होने से इसकी बहन की शादी की खुशी का प्रसंग शोक में बदल गया। घटना की वजह से घटना स्थल पर लोगों की भीड़ पहुंच गई। कार बस स्टेन्ड में घुसकर टकरा गई थी और जेसीबी की मदद से कार को बस स्टेन्ड से बाहर निकालना अनिवार्य हो गया । कार में से सिर्फ युवकों की लाश बाहर निकाली जा सकी । सभी मृतक युवकों के शव को पोस्टमोर्टम के लिए निकट के अस्पताल में भेजा गया। घटना मामले में स्थानीय पुलिस को जानकारी मिलने पर वह भी स्टाफ के काफिले के साथ वहां पहुंच गई और जरूरी जांच शुरू कर दी। जिसमें प्राथमिक जांच में चार में से दो युवक लोहार परिवार के थे, जबकि दो युवक मांगरोल के शक्तिनगर में रहते रबारी परिवार के थे। जो दो युवक लोहार परिवार के थे और इस दुर्घटना में मौत हो गई इसमें से एक युवक की बहन की आज शादी थी। शादी के दिन ही भाई के मौत से लुहार परिवार में शोक की लहर फैल गई और खुशी का प्रसंग शोक में बदल गया। शादी की खुशी का प्रसंग शोक में तब्दील हो गया। एक साथ चार मृतक युवकों की मौत की घटना की वजह से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।

बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त पर शादी प्रसंग कई रखे गये। वाहनमालिकों और अलग-अलग गाड़ियों को किराये पर चलाने वाले को भी कमाई हुई थी।

पीयावा गांव में मां ने संतानों के साथ जहरीली दवाई पी

अहमदाबाद । जूनागढ़ के विसावदर के पीयावा गांव में सामूहिक आत्महत्या की घटना सामने आई है। एक परिवार की मां ने दो बच्चों के साथ जहरीली दवाई पी लेने से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। जहरीली दवाई की असर की वजह से उपचार के दौरान मां और इसके छह वर्ष के पुत्र की मौत हो गई थी। जबकि इस घटना में मां की छोटी बेटी बच गई थी लेकिन बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस तरह जहरीली दवाई पीकर सामूहिक आत्महत्या की घटना में मां और इसके दो संतान इस तरह तीन लोगों की मौत होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। पुलिस की प्राथमिक जांच में घर के कलह से परेशान होकर मां ने संतानों के साथ जहरीली दवाई पी ली यह बात सामने आ रही है। हालांकि स्थानीय पुलिस ने आत्महत्या के पीछे असली वजह जानने की दिशा में जांच शुरू कर दी है। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, जूनागढ़ जिले के विसावदर के पीयावा गांव में एक मां ने दो बच्चों के साथ ज हरीली दवाई पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था।

महीसागर में बाराती से भरी टैम्पो पलटने से दो की मौत

अहमदाबाद,१० फरवरी।

राज्य में रोजाना घातक और भीषण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, तब रविवार को महीसागर में लीमडीया वीरपुर हाईवे पर टैम्पो में जा रहे बारातियों के लिए अशुभ साबित हुई । लीमडीया वीरपुर हाईवे पर यह टैम्पो अचानक पलटने से इस दुर्घटना में घटना स्थल पर ही दो व्यक्तियों की मौत हुई थी । जबकि अन्य ४० लोग घायल हो गए थे । इस घटना की वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई । इस दुर्घटना की वजह से घटना स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई, दूसरी तरफ घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में ले जाने के लिए १०८ या अन्य वाहन आये उसके पहले ही महिला, बच्चे सहित के घायल को रोड पर ही सुलाया गया और घायल लोग चीख-पुकार की हालत में देखने को मिले । इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, महीसागर जिले में लीमडीया वीरपुर हाईवे पर रविवार को सुबह में एक टैम्पो भरकर बारात जा रही थी, तब किसी वजह से टैम्पो ड्राइवर ने स्टियरिंग पर से नियंत्रण गंवाने से टैम्पो पलट गई थी । अचानक टैम्पो पलटने से अंदर बैठे बारातियों को भी टैम्पो नीचे दबने के साथ जमीन पर गिर गये थे । लीमडीया वीरपुर हाईवे पर यह टैम्पो अचानक पलटने से इस दुर्घटना में घटना स्थल पर ही दो व्यक्तियों की मौत हुई थी । जबकि अन्य ४० लोग घायल हो गए थे । इस घटना की वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई । इस दुर्घटना की वजह से घटना स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई, दूसरी तरफ घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में ले जाने के लिए १०८ या अन्य वाहन आये उसके पहले ही महिला, बच्चे सहित के घायल को रोड पर ही सुलाया गया और घायल लोग चीख-पुकार की हालत में देखने को मिले । इस दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जबकि ४० लोग कुछ हद तक घायल हो गये थे । जिसमें महिला, बच्चे सहित के लोग शामिल है । घटना की जानकारी मिलने पर लोगों की भीड़ एकत्र होकर दुर्घटना में घायल हुए सभी लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया । स्थानीय निवासियों में हो रही चर्चा के अनुसार, बारातियों को लेकर जा रहे यह टैम्पो का व्हील अचानक निकल जाने से ड्राइवर ने स्टियरिंग पर से नियंत्रण गंवा दिया था और टैम्पो अचानक पलट गई थी।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)**